



दी नैक्स पोस्ट

साप्ताहिक

7 4 हजार मरीज बिना इलाज के वापस लौटे 5 आंखों में धूल झोंक रही बुआ 8 जर्सी की एक्सचेंज

UPHIN51019

वर्ष: 02, अंक: 08

पृष्ठ संख्या: 08

मूल्य: 1.00 रु.

सोमवार 19 अगस्त, 2024

कोलकाता मर्डर केस की आंच बांग्लादेश तक पहुंची

ढाका की सड़कों पर ट्रेनी डाक्टरों ने किया प्रदर्शन



बांग्लादेश में फैली अशांति के बीच कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार के खिलाफ ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए। ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को आवाज तोलो नारी (महिलाओं अपनी आवाज उठाओ) के बैनर तले ढाका विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने कहा कि आरजी कर अस्पताल में हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का वो समर्थन कर रहे हैं।

आर जी कर अस्पताल में डॉक्टरों की मांग के समर्थन में जुटे छात्र।

ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन

पीटीआई, ढाका। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में देशभर में उबाल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी शनिवार को देशभर के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में हड़ताल की घोषणा की है।

पिछले कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किए। इस घटना का असर बांग्लादेश में भी दिख रहा है। ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार पर प्रदर्शन किए।

बांग्लादेश में महिला डाक्टरों ने क्या विरोध प्रदर्शन ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को "आवाज तोलो नारी" (महिलाओं, अपनी आवाज उठाओ) के बैनर तले ढाका विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन हुआ। ढाका ट्रिब्यून ने कहा, "पश्चिम बंगाल

में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले के संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के असहयोगात्मक रवैये से अवगत हैं। महिलाओं के रूप में हम इस घटना का कड़ा विरोध कर रहे हैं।"मानवविज्ञान विभाग की छात्रा अन्या फहमीन ने कहा, "दुनिया भर में महिलाओं को दुष्कर्म का सामना करना पड़ता है, और हम कोलकाता में आरजी कर अस्पताल मामले में निष्पक्ष जवाबदेही के लिए चल रहे आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं।"

बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन के बाद बदल गई सरकार

बता दें कि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में छात्रों ने नौकरी में आरक्षण में अनियमिता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बीच शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। फिलहाल वहां मुहम्मद युनुस की अंतरिम सरकार चल रही है।

केंद्र की डाक्टरों से काम पर लौटने की अपील

सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमेटी के गठन की तैयारी

नई दिल्ली। डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के बीच केंद्र सरकार की डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील, सुरक्षा के लिए कमेटी बनेगी। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म-हत्या के मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए), रेजिडेंट डॉक्टरों एसोसिएशन (आरडीए) समेत डॉक्टरों के कई संगठनों की तर्फ से जारी देशव्यापी हड़ताल का असर दिखने लगा है। केंद्र सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए डॉक्टरों से जल्द से जल्द काम पर लौटने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि फोर्डा, आईएमए और सरकारी अस्पतालों के आरजीए की तर्फ से बताई गई चिंताओं के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रहा है। यह कमेटी स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सभी संभव कदमों का ब्योरा देगी। इस कमेटी को सुझाव देने के लिए अलग-अलग प्रतिनिधियों और राज्य सरकारों का भी स्वागत है। मंत्रालय प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से अपील करता है कि वह जनहित के लिए ड्यूटी-मलेरिया के बढ़ते केंसों के मद्देनजर काम पर लौटें। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में देशभर के डॉक्टरों का गुस्सा उफान पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। आईएमए ने देश के सभी डॉक्टरों को 24 घंटे के लिए सेवाएं वापस लेने की घोषणा की। आपात सेवाएं जारी रहेंगी। ओपीडी भी बंद रहेंगी और वैकल्पिक सर्जरी को भी टाल दिया जाएगा।

नवाब के वकील ने पुलिस पर की सवालों की बौछार

पूछा- घटनास्थल पर तीन लोग, तो चौथे ने कैसे वीडियो बनाया



शुरू हो गई है। नवाब ने बिना कोई समय गंवाए मंजूरी दे दी

सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अदालत से बाहर आने के बाद बचाव पक्ष के वकील शिवकुमार ने कहा कि उनके मुक्किल को गलत आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी का डीएनए जांच कराने की मांग की। नवाब ने बिना कोई समय गंवाए मंजूरी दे दी।

पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में

वकील के मुताबिक यह दर्शाता है कि आरोपी को यकीन है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए अपनी जांच के लिए फोरन तैयार हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से कार्रवाई की है, वह अपने आप ही सवालों के घेरे में है।

चौथा व्यक्ति कौन था, जिसने वीडियो बनाया

आरोपी को उसके कॉलेज से पकड़ने पुलिस पहुंची तो वहां आरोपी, पीड़िता और उसकी बुआ थीं। फिर वह चौथा व्यक्ति कौन था, जिसने वहां का वीडियो बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। अगर यह पुलिस ने बनाया, तो यह उसकी जांच का विषय था।

संवाददाता, कन्नौज। कन्नौज जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में घिरे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने पुलिस पर सवालों की बौछार कर दी। हिरासत में लेने, गिरफ्तार करने, मौके का वीडियो वायरल होने, पीड़ित किशोरी के बयान के समय और उसके साथ मौजूद महिला को मौके पर ही न पकड़ने से जुड़े सवाल दागे गए। अदालत ने बचाव पक्ष के वकील से शनिवार को आपात दाखिल करने को कहा है। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को करीब एक घंटे तक बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील शिव कुमार ने शुक्रवार को अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस से जो सवाल किए उस पर चर्चा

हैवानियत की हर्से पार: इसलिए सिर काटकर की दोस्त की हत्या... फिर चाकू से निकाली आंखें, नाक-कान काट छील दी खोपड़ी



गाजियाबाद में दिल दहलाने वाली वारदात हैवानियत की सारी हर्से पार

दिल्ली-एनसीआर। साहिबाबाद की टीलामोड़ थाना पुलिस ने पंचशील कॉलोनी के जंगल में 22 जून की सुबह अज्ञात युवक का सिर कटा लहलुहान शव मिलने के मामले में हैरतअंगेज खुलासा किया है। गाजियाबाद से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। साहिबाबाद के टीला मोड़ थाना इलाके के पंचशील कॉलोनी के जंगल में 22 जून को मिले सिर कटे शव के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। शव की पहचान राजू कुमार (29) पुत्र भैरव शाह निवासी बिशनपुर थाना पिपरा जिला मोतिहारी बिहार के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि तंत्र विद्या से रुपये कमाने के लिए ई-रिक्शा चालक विकास उर्फ परमात्मा ने ऑटो चालक विकास और उसके दोस्त धनंजय को तरीका बताया था।

इसके बाद विकास और धनंजय ने पांच दिन तक शराब पिलाने के बाद पड़ोस में रहने वाले दोस्त राजू की हत्या कर दी थी। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि विकास उर्फ मोटा निवासी गली नंबर-एक ताहिरपुर थाना दिल्ली, उसके

दोस्त धनंजय पुत्र समासेनी निवासी हुसैनी थाना डुमरियाघाट जिला मोतिहारी बिहार को गिरफ्तार किया है। विकास ने पूछताछ में बताया कि वह अपने मामा मुन्ना का ऑटो किराये पर लेकर चलाता है। कुछ महीने पहले उसकी मुलाकात धनंजय से हुई थी। वह कमला मार्केट, नई दिल्ली के पास गढ़ी हिम्मतगढ़ में अपने दूर के रिश्ते के मामा के पास रहकर खाना बनाता है। इसी बीच दोनों की मुलाकात विकास उर्फ परमात्मा निवासी ताहिरपुर दिल्ली से हुई। परमात्मा इन दोनों से तंत्र विद्या और टोने-टोटके से सब कुछ हासिल करने की बात कहता रहता था। वह उनसे कहता था कि एक दिन दोनों को बड़े काम से पैसे मिलेंगे। उसने दोनों को बताया कि ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसकी हत्या करके खोपड़ी काटने के बाद तंत्र क्रिया की जा सके। उसने धनंजय को अज्ञात युवक की तलाश के लिए पांच लाख रुपये देने का लालच भी दिया। दोनों एक साथ युवक की तलाश करने लगे। इस

दौरान धनंजय ने अपने पड़ोसी और दोस्त राजू कुमार को निशाना बनाने के लिए जाल में फंसाया शुरू कर दिया। राजू नशा करने का आदी था और वह पकौड़े की टेली लगाता था। दोनों 15 जून को राजू को अगवा कर परमात्मा के कमरे में ले गए। वहां पांच दिन तक उसे शराब पिलाते रहे। 21-22 जून की रात कमरे में राजू को गले में फंदा लगाकर पंखे से लटका दिया। बाद में तीनों उसके शव को छिपाने के लिए ऑटो से टीला मोड़ थाना क्षेत्र की पंचशील कॉलोनी में पहुंचे। वहां पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से सड़क किनारे ऑटो खड़ा कर राजू का सिर छुरी से काटकर धड़ जंगल में फेंककर फरार हो गए थे। तीनों उसके सिर को प्लास्टिक की बाल्टी में रखकर ले गए।

सात दिन तक कमरे में रखा था कटा सिर एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि राजू का सिर काटने के बाद तीनों ने उसे सात दिन तक कमरे में रखा। जब कमरे में बदबू फैलने लगी तो मुख्य आरोपी विकास और परमात्मा ने तंत्र विद्या से पैसे कमाने का तरीका आजमाया लेकिन वह कुछ घंटे प्रयास के बावजूद सफल नहीं हुआ। इसके बाद वह कटा हुआ सिर लेकर भाग गया। हत्याकांड में आरोपियों ने ई-रिक्शा का भी इस्तेमाल किया था।

पुलिस ने दर्ज नहीं की थी राजू की गुमशुदगी पुलिस का कहना है कि राजू के माता-पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। वह ताहिरपुर में अपने फूफा गणेश के पास रहता था। 15 जून की देर रात तक जब राजू घर नहीं पहुंचा था तो उसकी गुमशुदगी कराने वह थाने पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने जांच की बात कह लौटा दिया था। फिलहाल पुलिस फरार विकास उर्फ परमात्मा की तलाश में दबिश दे रही है।

सम्पादकीय

रोजगारविहीन विकास की रणनीति पर नरेंद्र मोदी सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कई बातें सामने आयी हैं, जिनमें से एक प्रमुख है वर्तमान में अपनायी जा रही रोजगार विहीन

एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ आबादी के एक छोटे से हिस्से के पास धन का अधिकाधिक संकेन्द्रण हो रहा था। आबादी का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा अब देश की सत्तर प्रतिशत (70प्रतिशत) संपत्ति का मालिक था। दुनिया में कहीं भी, अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है। भारत को ‘एकाधिकार पूंजीवाद’ के रास्ते पर ले जाया जा रहा है! सुविधाकर्ता ‘भारत सरकार’ है। अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक हर हवाई अड्डा अब अडानी समूह का है। हवाई यात्रा की लागत में अचानक वृद्धि के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में कई बातें सामने आयी हैं, जिनमें से एक प्रमुख है वर्तमान में अपनायी जा रही रोजगार विहीन विकास की रणनीति जिसके कारण बेरोजगारी की ऊंची दरको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। वर्ष 2014 में चुनाव के लिए प्रचार के दौरान, नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से कई वायदे किए थे। उनके द्वारा किये गये सबसे प्रमुख वायदों में से एक था हर साल दो करोड़ नौकरियों का सृजन करना। अपने वायदे के अनुसार, दस वर्षों में उन्हें और उनकी सरकार को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए जाने से पहले (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) बीस करोड़ नौकरियां (दो सौ मिलियन नौकरियां) पैदा करनी चाहिए थीं। अपने कई वायदों की तरह, पीएम ने बहुत ही चतुराई और सुविधापूर्वक इस वायदे को भूलने का विकल्प चुना। वास्तव में उनके कई नीतिगत निर्णयों के कारण रोजगार में गिरावट आयी, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि पिछले चालीस वर्षों में बेरोजगारी सबसे अधिक बढ़ गयी। देश में रोजगार में गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पीएसयू) को बेचना था। स्वतंत्र भारत में किसी अन्य सरकार ने इतने सस्ते दरों पर इतने सारे पीएसयू नहीं बेचे। कुल मिलाकर इसका असर न केवल उत्पादकता पर पड़ा, बल्कि रोजगार पर भी पड़ा। लाखों युवा बेरोजगार रह गये!

एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, दूसरी तरफ आबादी के एक छोटे से हिस्से के पास धन का अधिकाधिक संकेन्द्रण हो रहा था। आबादी का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा अब देश की सत्तर प्रतिशत (70प्रतिशत) संपत्ति का मालिक था। दुनिया में कहीं भी, अमीर और गरीब के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं है। भारत को ‘एकाधिकार पूंजीवाद’ के रास्ते पर ले जाया जा रहा है! सुविधाकर्ता ‘भारत सरकार’ है। अहमदाबाद से लेकर कोलकाता तक हर हवाई अड्डा अब अडानी समूह का है। हवाई यात्रा की लागत में अचानक वृद्धि के खिलाफ उंगली उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कॉरपोरेट समर्थक आर्थिक नीतियों से जो निकला, वह ‘बेरोजगारी वाला विकास’ का एक पाठ्यपुस्तक मामला था। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हम जल्द या थोड़ी देर से ‘पांच ट्रिलियन’ की अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, फिर भी हमारे युवा बेरोजगार रहेंगे! पिछले साल जब फ्रांस में पर्याप्त नौकरियों नहीं बनीं और मौजूदा नौकरियों में ‘हायर एंड फायर’ की नीति लायी गयी, तो देश का पूरा युवा बेहतर नौकरी और बेहतर वेतन की माँग को लेकर सड़कों पर उतर आया। एक पूरे हफ़्ते तक फ्रांस में ज़िंदगी ठहर सी गयी थी। आख़रि़कार मैक्रोन की सरकार ने युवाओं की माँगों के आगे घुटने टेक दिये। ‘हायर एंड फायर’ की नीति को समय की गारंटी से बदल दिया गया। तभी स्थिति सामान्य हो सकी। नौकरियाँ बहुत जरूरी हैं! जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो सबसे पहले आकस्मिक कामगारों को मंदी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को सबसे पहले घर भेजा जाता है। फिर अस्थायी कामगारों का नंबर आता है। चूंकि असंगठित क्षेत्र में कोई यूनियन नहीं है, इसलिए गरीब कामगार ठेकेदारों की दया पर निर्भर हैं। रिपोर्ट कहती है कि जब भी बाजार में उथल-पिथल होती है, तो सबसे कम आय वाले लोगों की आय में सबसे ज्यादा गिरावट आती है। मोदी सरकार ने एक और चाल चली है। गरीब लोगों को शिक्षा से दूर रखकर। ऐसे लोगों की रोजगार क्षमता कम हो जाती है। यह एक अवलोकन है कि जब युवा ठीक से शिक्षित नहीं होते हैं तो वे सबसे कम पारिश्रमिक पर जल्दी नौकरी की तलाश करते हैं। यह निजी कंपनियों के लिए अच्छा है। जब कोई बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई किसी निजी कंपनी को सौंपी जाती है, तो सबसे पहले नया मालिक कर्मचारियों की संख्या कम कर देता है। इससे तुरंत लाभ की सीमा बढ़ जाती है। चूंकि काम वही रहता है, इसलिए मौजूदा कर्मचारियों को लंबे समय तक काम पर रहना पड़ता है। पूंजीवाद समर्थक रसंतकार तुरंत निजी खिलाड़ियों के अधीन कंपनी की कार्यकुशलता के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। वे चतुराई से इस तथ्य को छिपाते हैं कि बहुत से कर्मचारियों की नौकरी चली गयी और शेष कर्मचारियों का प्रतिदिन शोषण किया जा रहा है। बढ़ा हुआ लाभ शोषित श्रमिकों के खून–पसीने की कमाई का प्रतिबिम्ब है। हाल ही में भारत के एक बड़े पूंजीपति ने बैंगलोर में सत्तर घंटे काम करने का आह्वान किया।सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने तुरंत इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाई। जियो को लाभ में लाने के लिए, बीएसएनएल के 70,000 कर्मचारियों को वीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के नाम पर घर भेज दिया गया। वास्तव में उस योजना को सीआरएस (अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजना) कहा जाना चाहिए था। कुछ समय तक जियो कम लागत पर सेवाएं देकर चमक सकता था। जब बीएसएनएल के ग्राहक जियो में बदल गये, तो असली खेल शुरू हुआ। अब जियो बहुत महंगा हो गया है और ग्राहक बीएसएनएल की ओर लौटना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बीएसएनएल में अब कर्मचारियों की कमी है। जब तक सरकार तुरंत नये कर्मचारियों की भर्ती नहीं करती, ग्राहकों को परेशानी होती रहेगी और युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। कुछ साल पहले तक भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की कुल संख्या 19 लाख थी। नई आर्थिक व्यवस्था शुरू होने के बाद भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या में लगातार कमी की गयी। आज भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या केवल 12 लाख रह गयी है। इस कमी का दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव सुरक्षा और सेवाओं पर पड़ा है। रेल पटरियों पर दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला इस बात का प्रमाण है कि मानव संसाधन के अभाव में सबसे अच्छा स्वचालन भी विफल हो जाता है। जिस देश में हमारे पास तकनीकी रूप से शिक्षित मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, वहां स्वचालन पर किसी भी तरह की निर्भरता अनावश्यक है। आज अधिकांश भारतीय युवा हैं। हमारी आबादी दुनिया में सबसे युवा है। इस स्थिति का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका हमारे युवा बेटे–बेटियों के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है। इससे न केवल देश की विकास दर बढ़ेगी बल्कि इस महान भूमि के लाखों घरों में ढेर सारी खुशियाँ भी आयेंगी।भारत तभी समृद्ध होगा जब भारतीयों का जीवन सुखी होगा!

आजादी के तोहफे पर सियासत का फीता

बांग्लादेश के नए मुखिया ने बिल्कुल नोबेल विजेता के अनुरूप ही बातें कही हैं। समस्याएं लोगों में नहीं व्यवस्था में होती है और उन गड़बड़ियों को दूर करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। व्यवस्था की कमियों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म की आड़ में ईसानों को अगर निशाना बनाया जाना लोकतंत्र की पहचान नहीं है। यह बात बांग्लादेश के लिए ही नहीं भारत के लिए भी की उत्तनी ही माकूल है। देश एक बार फिर आजादी की वर्षगांठ मनाने तैयार है। 2014 से पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जनता के उत्सव हुआ करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में माहौल बदल गया है। अब इन राष्ट्रीय पर्वो को अनाधिकारिक तरह से भाजपा के अधिकार क्षेत्र के दायरे में मनाया जाने लगा है। 2 अक्टूबर का महत्व भी भाजपा ने लगभग खत्म ही कर दिया है, क्योंकि अब चरखा चलाने गांधी की जगह खादी वाले मोदी के कैलेंडर का चलन देश में हो गया है। 2021 से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने की शुरुआत नरेन्द्र मोदी ने की और उसके बाद तो जैसे आजादी पर भाजपा का कॉपीराइट ही हो गया। अमृत महोत्सव के बाद हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई। अब 15 अगस्त के कुछ दिनों पहले से तिरंगा यात्राएं निकाली जाने लगी हैं, जिनमें भाजपा नेता और उनके समर्थक बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मेरा तिरंगा उसके तिरंगे से बड़ा क्यों नहीं, बस यही सफाई खुलकर शुरु होना बाकी है, वर्ना दिखावे में कोई किसी से पीछे नहीं है।

तिरंगा फहराने में किसी नागरिक को कोई आपत्ति नहीं है, यह जरूर है कि संघ को इससे आपत्ति थी और शायद इसलिए संघ मुख्यालय में तिरंगा 2002 तक नहीं फहराया गया, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई। इस बारे में पिछले साल जब मोहन भागवत से सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि हम जहां रहते हैं, वहां तिरंगा फहराते हैं। सवाल तिरंगा फहराने का नहीं है, लेकिन जब इसकी रक्षा की बात आए, तो हम सबसे आगे रहते हैं। श्री भागवत ने एक सीधे सवाल का जवाब गोल–मोल तरीके से दे दिया। यही गोल–मोल रवैया अब मोदी सरकार का भी दिख रहा है। 2021 से ही नरेन्द्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत भी की। हर साल 14 अगस्त को अखबारों में बड़े–बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें बंटवारे की भयानक याद को ताजा किया जाता है। इस बरस भी यही हुआ। देश के

दो हिस्से होने के बाद लाखों लोगों को अपनी जड़ों से उखड़कर किस तरह विस्थापित होना पड़ा, इसकी तस्वीरें नरेन्द्र मोदी की तस्वीरों के साथ दी गईं। भाजपा की इस मानसिकता को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है कि बुरी यादों को वह किस तरह राजनीति के लिए इस्तेमाल करती है और उसमें विध्वंसक शब्दों का जो खिलवाड़ होता है, वह भी आश्चर्य ही है। संविधान हत्या विरोधी दिवस भाजपा का ताजा दांव है, जिसमें आपातकाल की याद लोगों को दिलाई जाएगी और इसके लिए हत्या जैसे शब्द का सहज इस्तेमाल भाजपा ने कर लिया। इसी तरह विभाजन की विभीषिका के साथ स्मृति शब्द जोड़ा गया। ऐसा नहीं है कि बंटवारे के दर्द को लोगों ने बाद में याद नहीं किया। भीष्म साहनी के लेखन का बड़ा हिस्सा बंटवारे पर ही है। सआदत हसन मंटो, कृष्णा सोबती, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, यशपाल जैसे कई लेखकों ने बंटवारे पर कहानियां, उपन्यास, नाटक लिखे। बंटवारे पर फिल्में, धारावाहिक भी बने। लेकिन सबमें मूल सवाल यही रहा कि सरहदें बंटने से क्या इंसानियत के मायने बदल जाते हैं। क्या कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा हो सकता है।

नरेंद्र मोदी को कभी अपने लिखे को पढ़ने से फुर्सत मिले, तो उन्हें विभाजन पर लिखे गए साहित्य को भी पढ़ना चाहिए, तब उन्हें यह अहसास होगा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत करके असल में उन्होंने फिर से बंटवारे की मानसिकता को ताजा करने का काम किया है। संघ की सोच तो हमेशा से अखंड भारत वाली रही है। हालांकि भू राजनैतिक परिस्थितियों को दरकिनार करके संघ किस तरह से इस सोच को अमल में लाएगा, यह भी एक अबूझ पहली है।

श्री मोदी ने इस बरस टवीट किया है कि हम उन अनगिनत लोगों को याद करते हैं जो विभाजन की भयावहता से प्रभावित हुए और उन्हें बहुत तकलीफ हुई। यह उनके साहस को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है, जो मानवीय लचीलेपन की शक्ति को दर्शाता है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन को फिर से संवारा और अपार सफलता प्राप्त की। आज, हम अपने देश में एकता और भाईचारे के बंधनों की हमेशा रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने कहा कि पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा

वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना औकाफ को विनियमित करने के लिए की गयी थी, जिसका अर्थ है वक्फ के रूप में दान की गयी और नामित वह संपत्ति जो एक वाकिफ द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधन विभिन्न राज्य निकायों में मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करके समावेशिता की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के कदम की धर्मनिरपेक्ष पार्टियों और मुस्लिम संगठनों दोनों ने कड़ी आलोचना की है। लेकिन यह इस तथ्य को भी उजागर करता है कि तथाकथित मुस्लिम नेता खुद अपने घर को सही करने के लिए तैयार नहीं हैं। कई राज्यों के वक्फ बोर्डों में कथित अनियमितताओं का फायदा उठाते हुए, सरकार ने इन नेताओं को देश की राजनीति में उनकी जगह दिखाने के लिए यह कदम उठाया है, इससे पहले ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर उन्हें कड़ी फटकार लगायी गयी थी। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार, वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किये गये सभी दावों का अनिवार्य सत्यापन किया जायेगा। वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गयी संपत्तियों के लिए एक अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया प्रस्तावित है। वक्फ अधिनियम, 1995 की स्थापना औकाफ को विनियमित करने के लिए की गयी थी, जिसका अर्थ है वक्फ के रूप में दान की गयी और नामित वह संपत्ति जो एक वाकिफ द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए समर्पित करता है। प्रस्तावित संशोधन विभिन्न राज्य निकायों में मुस्लिम महिला सदस्यों को शामिल करके समावेशिता की बात करते हैं।

दरअसल, मुस्लिम खुद इसके खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि इस्लाम एक महिला को मुतवल्ली – वक्फ संपत्ति का प्रबंधक या किसी वक्फ बोर्ड का सदस्य होने की अनुमति देता है, क्योंकि यह एक प्रबंधकीय पद है और इसके लिए इस्लामी कानूनों के किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा दिल्ली स्थित इस्लामिकफिकह अकादमी से जुड़े एक मुफ्ती ने बताया। दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में भी कई महिला सदस्य हैं, उन्होंने आगे कहा। इसलिए, यह बहाना व्यापक आबादी को गुमराह करने के लिए है कि मुसलमान विभिन्न वक्फ निकायों में एक महिला सदस्य को शामिल करने के खिलाफ हैं।

इस विधेयक को लाने की नींव पिछले साल तब रखी गयी थी जब मार्च 2023 में वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गयी थी। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि वक्फ अधिनियम के एक या अधिक प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 120 रिट याचिकाएं देश की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। उपाध्याय ने वक्फ अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी थी और केंद्र से ‘ट्रस्ट और ट्रस्टी, दान और धर्मार्थ संस्थाओं, और धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थाओं के लिए एक समान कानून’ बनाने का निर्देश मांगा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन की आड़ में बनाया गया था, लेकिन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, बहाई धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के अनुयायियों के लिए समान कानून नहीं थे। ‘इसलिए, यह राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता के खिलाफ है।’ यहां, यह पृष्ठने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सरकार भारत भर में विभिन्न ट्रस्टों को विनियमित करने के लिए उसी आधार पर तैयार होगी, जो बर्दीनाथ/केदारनाथ से लेकर तिरुपति तक विभिन्न मंदिरों का प्रबंधन करते हैं। क्या यह इन ट्रस्टों को महिला सदस्यों को शामिल करने के लिए मजबूर कर पायेगी, ताकि समावेशिता बढ़े? मामले को और जटिल बनाने और मुस्लिम समुदाय के बीच कलह के बीज बोने के लिए, सरकार कथित तौर पर बोहरा, आगाखानी और अन्य के लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन करना चाहती है। सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन की तैयारी के बीच, अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कानून में संशोधन के लिए ‘गरीब मुस्लिम समूहों’ की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है। लेकिन वे इन ‘गरीब मुस्लिम समूहों’ की पहचान करने में विफल रहे। संशोधनों का समर्थन करने के लिए अब तक एकमात्र समूह अखिल भारतीय सूफ़ी सज्जादानशीन परिषद (एआईएसएससी) है, जिसने सरकार के कदम का स्वागत किया है और निहित स्वार्थों पर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का आरोप लगाया है। लेकिन एआईएसएससी भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसके सदस्य के रूप में विभिन्न संप्रदायों के मुस्लिम मौलवी नहीं हैं।

प्रस्तावित कानून केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में ‘मुस्लिम और गैर–मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व’ सुनिश्चित करेगा। अब मुसलमानों के कल्याण से संबंधित संगठन में गैर–मुस्लिम सदस्यों को क्यों शामिल किया जाना चाहिए? एक बार फिर, पहले वाला सवाल उठता है कि क्या हिंदू मंदिर और धार्मिक ट्रस्ट किसी भी मुस्लिम को अपना सदस्य बनने की अनुमति देंगे? आलोचना से बचने के लिए सरकार यह तर्क देती है कि वह न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और केआर रहमान की अध्यक्षता वाली वक्फ और केंद्रीय वक्फ परिषद पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर काम कर रही है, हालांकि उनकी सिफारिशों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद वर्ष 2013 में अधिनियम में व्यापक संशोधन किये गये थे। भारत भर के अधिकांश मुस्लिम संगठनों ने प्रस्तावित संशोधनों की तीखी निंदा की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीनऔवैसी ने प्रस्तावित विधेयक की निंदा करते हुए भाजपा पर ‘हिंदुत्व एजेंडा’ चलाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दल भी इसके खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि च्हम इसके (वक्फ अधिनियम संशोधन विधेयक) खिलाफ होंगे। आईयूएमएल के ई. टी. मोहम्मदबशीर ने कहा कि सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम गलत इरादे से उठाया गया है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंकाचतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार बजट पर चर्चा से भागना चाहती है और इसलिए वे वक्फ मुद्दे को लेकर आयी है।

सीपीआई (एम) सांसद अमरा राम ने कहा कि भाजपा च्विभाजनकारी राजनीतिज्ज में विश्वास करती है और वक्फ बोर्डों को मजबूत करने के बजाय, वे उनमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। एक अन्य सीपीआई (एम) सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का एकमात्र इरादा विभाजनकारी एजेंडे को बढ़ावा देना है। जेएमएम की महुआ माजी ने कहा कि एकतरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए और अगर कोई संशोधन किया जाना है, तो सरकार को सभी पक्षों की बात सुननी चाहिए। पंजाब वक्फ बोर्ड के सदस्य हाशिम सूफ़ी ने कहा कि सरकार इस तरह के कदम उठाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने पर आमादा है, जबकि वह इस बात को नजरअंदाज कर रही है कि वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित संपत्तियों और संस्थानों का लाभ हिंदुओं और सिखों सहित सभी समुदायों के सदस्यों को समान रूप से मिलता है। जमीयतउलेमा–ए–हिंद ने जोर देकर कहा कि वक्फसंपत्तियों की स्थिति और प्रकृति में कोई भी बदलाव लाना या सरकार या किसी व्यक्ति के लिए उनका च्छदुरूपयोगज्ज करना आसान बनाना अवैकीकार्य है। प्रमुख मुस्लिम निकाय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर वक्फ बोर्डों को कमजोर करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है।

या फिर हमेशा के लिए इतिहास से समाप्त हो जाएगा। भाजपा के इन दो नेताओं के वक्तव्यों से समझ आता है कि असल में इनके लिए आजादी का महत्व सत्ता से जुड़ा हुआ है और इसमें विभाजन के दिन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना पड़े तो यह भी इन्हें मंजूर है। देश में एकता और भाईचारे की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी चुनावी भाषणों में कपड़ों से पहचान की बात भी करते हैं और जिनके ज्यादा बच्चे होंगे, कांग्रेस उन्हें आपका धन दे देगी, जैसे बयान भी देते हैं। गनीमत है कि देश की जनता ने इन चुनावों में ऐसे भाषणों को तरजीह नहीं दी। वैसे भी भारत की जनता आजादी और लोकतंत्र दोनों का महत्व अच्छे से समझती है। खासकर मौजूदा वैश्विक हालात देखकर यह बात और गहराई से समझी जा सकती है कि एक आजाद और लोकतान्त्रिक देश में रहने के क्या मायने होते हैं। इजरायल के आक्रमण से फिलीस्तीन के लोगों की जो दशा हुई है, शायद नारकीय शब्द भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपने क्रूर शासक की सरपरस्ती में इजरायली सैनिक नृशंसता की सारी हदें पार कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं बतकही से काम चला रही हैं। अमेरिका की शह पर युद्ध का धिनौना खेल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर रूस और यूक्रेन में भी किसी तरह युद्ध विराम नहीं हो रहा, बल्कि यूक्रेन रूस की सीमाओं के भीतर आ गया है, जिससे साफ हो गया है कि नाटो का खतरेनाक खेल इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। हमारे अपने पड़ोसी बांग्लादेश में जिस तरह से तख्तापलट किया गया, वह चिंताजनक है ही, उससे भी खतरनाक बात यह है कि वहां धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा हो रही है। जबकि बांग्लादेश अपने गठन की शुरुआत से धर्मनिरपेक्षता को लेकर चला है। मगर सत्ता की आड़ में धर्मांध तत्वों ने वहां भी घुसपैठ कर ली। गनीमत यह है कि वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद युनुस ने 13 अगस्त को ढाकेश्वरी मंदिर जाकर अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि वे उनके हितों की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। मो.युनुस ने कहा कि ‘हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू या बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के तौर पर में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं के क्षय में है। इसीलिए ऐसे मुद्दे उठते हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है।’

हड़ताल: गोरखपुर बीआरडी में स्थिति बिगड़ी, एम्स में 50 आपरेशन टले

4 हजार मरीज बिना इलाज के वापस लौटे



एम्स में ओपीडी बंद होने के कारण इमरजेंसी में बढ़ी मरीजों की भीड़। -

गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने सभी विभागों की ओपीडी को जबरन बंद करा दिया। सुबह सात बजे से नौ बजे तक जिन मरीजों ने पर्ची कटा लिया, उन्हीं का इलाज हो सका। प्राचार्य के मना करने के बाद भी जूनियर डॉक्टर नहीं माने। करीब 2500 से अधिक मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ा। एम्स की ओपीडी बंद होने से लगभग 1500 मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के विरोध में शुक्रवार को भी एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का हड़ताल जारी रहा। बीआरडी में जूनियर डॉक्टरों ने पर्चा काउंटर बंद कराकर ताला लगा दिया। एम्स में ओपीडी में भी नहीं गए, सीनियर डॉक्टरों ने मोर्चा संभाला। पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले मरीजों को देखा गया। बीआरडी में ओपीडी सिर्फ दो घंटे चल सकी। एम्स में 50 आपरेशन नहीं हो सके। कुछ मरीजों के परिजनों ने डिस्चार्ज कराकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। दूर-दराज

से आए मरीजों को सांसत उठानी पड़ी। इमरजेंसी में भी अव्यवस्था बनी रही। पूरे दिन अफरा-तफरी की स्थिति रही। उधर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स में हड़ताल से जिला अस्पताल में भीड़ बढ़ गई। एम्स में एमबीबीएस छात्र, सीनियर रेजिडेंट, इंटरन डॉक्टरों ने ओपीडी के बाहर सुबह नौ बजे से प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे ओपीडी में जाने का रास्ता बंद हो गया। मरीज ओपीडी में जाने के लिए परेशान होने लगे। इस दौरान मरीज, गाडों से ओपीडी में जाने का रास्ता भी पूछते नजर आए। डॉक्टरों की हड़ताल से ऑफलाइन ओपीडी पूरी तरह से बंद रही। ऑनलाइन पर्चे पर कुल 1124 मरीज ही डॉक्टर को दिखा पाए।

वहीं, सिर्फ नौ आपरेशन ही हुए। 50 मरीजों का आपरेशन टाल दिया गया। इन मरीजों को आपरेशन के लिए दूसरी तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही ओपीडी नहीं चलने के कारण करीबन 1500 से अधिक मरीजों को बगैर इलाज कराए घर लौटना पड़ा। इमरजेंसी में भी इलाज नहीं मिल पाने के कारण कई मरीजों को प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाना पड़ा। एमबीबीएस छात्र, सीनियर रेजिडेंट, इंटरन डॉक्टरों ने शाम पांच बजे एम्स से मोहदीपुर तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। कैंडल मार्च में एम्स के विभिन्न विभागों के डॉक्टर शामिल हुए। डॉक्टरों ने घटना की निंदा करते हुए इंसाफ की मांग की।

इंटरशिप कर रहे डॉ. शशांक शेखर ने कहा कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग कर रहे हैं। डॉ. केदार ने कहा कि हम दोषियों को सजा दिलाने के साथ पांच मांग कर रहे हैं। अक्सर मरीज के साथ आए लोग प्रभावशाली लोगों की धौंस दिखाकर इलाज की मांग करते हैं। महिला डॉक्टरों को इलाज के साथ सुरक्षा, गलत व्यवहार और अपशब्द सुनने पड़ते हैं। डॉक्टरों को 24 घंटे की ड्यूटी के दौरान आराम करने की सुरक्षित जगह, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो

जूनियर डॉक्टरों ने सुबह नौ बजे नेहरू चिकित्सालय का पर्ची काउंटर पर ताला जड़कर किया। इसके बाद हालात की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य राजकुमार जायसवाल ने डॉक्टरों को ऐसा करने के लिए मना किया। इसके बाद भी डॉक्टर हड़ताल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए। जूनियर डॉक्टर कैंपस में आने वाले मरीजों के साथ विभागों में जाकर भी उन्हें वापस भेजने लगे। डॉक्टरों ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और बाल सेवा संस्थान को बंद करवा दिया। सुबह दस बजे से बाबा राघव दास की प्रतिमा के पास पोस्टर बैनर लेकर डॉक्टरों ने 'सेव द सेवियर' वी वांट जस्टिस के साथ दोषी को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए नारे लगाए। प्राचार्य, बीआरडी मेडिकल कॉलेज राजकुमार जायसवाल ने कहा कि सभी सीनियर डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं। ओपीडी में मरीजों को देखा भी गया। हमारा पूरा प्रयास है कि अधिक से अधिक मरीजों को राहत दी जा सके।

कनवेशन सेंटर निर्माण में सुस्ती

गोरखपुर। रामगढ़ताल के किनारे चंपा देवी पार्क एवं वॉटर स्पोर्ट्स की खाली पड़ी 25 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाना है। फरवरी 2024 में निर्माण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली के आधार पर तीन कंपनियों के बीच से क्वानो एवं जेएमटी रियल प्राइवेट लिमिटेड, विकास खंड, गोमतीनगर, लखनऊ का चयन किया गया था। कंपनी को तीन वर्ष में निर्माण

माह में बैंक गारंटी 15 करोड़ एवं रिजर्व प्राइज मनी 51 करोड़ 51 लाख रुपये प्राधिकरण में जमा करने थे। निर्धारित तीन माह की अवधि मई में ही समाप्त हो गया। लेकिन, बीच में चुनाव आचार संहिता के चलते फर्म को अतिरिक्त समय दिया गया। 15 जुलाई को प्राधिकरण ने फर्म को पत्र जारी कर एक सप्ताह में सभी औपचारिकताएं पूरी करने का आदेश दिया। इसके बाद भी फर्म ने न तो परफॉर्मेंस गारंटी जमा कराई और ना ही अपफ्रंट प्रीमियम की धनराशि को ही जमा करा



पूरा करना था। रामगढ़ताल के किनारे प्रस्तावित विश्वस्तरीय कनवेशन सेंटर के निर्माण एवं संचालन की जिम्मेदारी जिस फर्म को मिली थी, उसे अनुबंध की प्रक्रिया का पालन न करना महंगा पड़ा। जीडीए ने फर्म को एक साल के लिए ब्लैक लिस्टेड करने के साथ उसकी ओर से जमा की गई जमानत धनराशि को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने नई फर्म के लिए चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। रामगढ़ताल के किनारे चंपा देवी पार्क एवं वॉटर स्पोर्ट्स की खाली पड़ी 25 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाना है। फरवरी 2024 में निर्माण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली के आधार पर तीन कंपनियों के बीच से क्वानो एवं जेएमटी रियल प्राइवेट लिमिटेड, विकास खंड, गोमतीनगर, लखनऊ का चयन किया गया था। कंपनी को तीन वर्ष में निर्माण पूरा करना था। इसके बाद उसको 33 वर्ष तक संचालन का जिम्मा मिलता। चयनित फर्म को वर्क आर्डर जारी होने के साथ तीन

सकें। प्राधिकरण के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि कनवेशन सेंटर के निर्माण एवं संचालन के लिए चयनित फर्म की ओर से अनुबंध की औपचारिकता पूरी न करने पर उसकी जमा धनराशि को जब्त कर लिया गया है। वहीं फर्म को एक वर्ष के लिए प्राधिकरण में निविदा में प्रतिभाग के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। **कनवेशन सेंटर निर्माण के बदले मिलेगी फाइव स्टार होटल की जमीन** चयनित फर्म को कनवेशन सेंटर एवं अन्य सुविधाओं के संचालन का अधिकार 33 साल के लिए लीज पर मिलेगा। कनवेशन सेंटर निर्माण के बदले फर्म को फाइव स्टार होटल के लिए 6.5 एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर दी जाएगी। होटल में न्यूनतम 150 कमरे रखने होंगे। यहां व्यावसायिक उपयोग भी किया जा सकेगा। कनवेशन सेंटर निर्माण करने वाली फर्म को 51 करोड़ रुपये प्राइज मनी प्राधिकरण में जमा करानी होगी। फर्म को तीन वर्ष में निर्माण पूरा होने के बाद संचालन करते हुए कंपनी हर वर्ष 12 करोड़ रुपये 10 वर्ष तक जीडीए को देगी। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि कनवेशन सेंटर निर्माण एवं संचालन के लिए चयनित फर्म को अनुबंध की औपचारिकता पूरा न करने पर उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही उसकी जमानत धनराशि का जब्त कर लिया गया है। वहीं नई फर्म को चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

न्यू कालोनी स्थित न्यू खुशी हास्पिटल सील नहीं मिला कोई प्रशिक्षित डाक्टर-पंजीकरण भी नहीं मिला

देवरिया। जिले में डीएम के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध अस्पतालों, क्लिनिक व जांच सेंट्रों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शहर के न्यू कॉलोनी स्थित एक हॉस्पिटल सील कर दिया गया। जांच के दौरान हॉस्पिटल पर कोई एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती नहीं मिली। साथी पैरामेडिकल स्टॉफ की जगह जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा की तैनाती मिली। जिले में डीएम के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध अस्पतालों, क्लिनिक व जांच सेंट्रों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शहर के न्यू कॉलोनी स्थित एक हॉस्पिटल सील कर दिया गया। जांच के दौरान हॉस्पिटल पर कोई एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती नहीं मिली। साथी पैरामेडिकल स्टॉफ की जगह जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा की तैनाती मिली। डीएम दिव्या मिश्रा के निर्देश पर जिले में चल रहे अभियान के क्रम में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरपी यादव शुक्रवार को पटल सहायक राय कमलेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव के साथ न्यू कॉलोनी स्थित न्यू खुशी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हॉस्पिटल पंजीकृत नहीं है और न ही पंजीकरण के लिए कोई आवेदन किया गया। मौके पर बरहज के जरार रमन गांव निवासी ममता यादव पत्नी संजीत यादव 11 अगस्त से भर्ती मिली। उसे सीजर से बच्चा हुआ है। जांच के दौरान मौके पर कोई प्रशिक्षित एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिला। पैरा मेडिकल स्टॉफ के रूप में बनकटा की जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्रा सोनी पत्नी जितेंद्र की तैनात मिली। इतनी खामियां मिलने के बाद अधिकारियों की टीम ने उक्त हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस दौरान हॉस्पिटल की संचालक शालू सिंह पत्नी सत्येंद्र सिंह भी मौजूद रही।

सिद्धार्थनगर व संतकबीर नगर जिले के जिलाधिकारियों ने निरस्त किए अविश्वास प्रस्ताव, यहां से भी नहीं मिली राहत

गोरखपुर। संतकबीरनगर में डीएम को प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कराने के संबंध में हाजरा खातून समेत तीन अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्रा और जयंत बनर्जी की बेंच ने इसे जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में खारिज कर दिया है। जबकि, सिद्धार्थनगर के डीएम ने कूट रचित प्रपत्रों के सहारे अविश्वास प्रस्ताव देने वालों पर केंस दर्ज करवा दिया है। सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के डीएम ने अपने-अपने जनपद में ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। सिद्धार्थनगर में नौगढ़ की ब्लॉक प्रमुख रेनु मिश्रा और संतकबीरनगर में सेमरियावां के ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था। दोनों ही अविश्वास प्रस्ताव उप क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 के तहत अस्वीकार कर दिए गए थे। संतकबीरनगर में डीएम को प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कराने के संबंध में हाजरा खातून समेत तीन अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंजनी कुमार मिश्रा और जयंत बनर्जी की बेंच ने इसे जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में खारिज कर दिया है। दरअसल, दोनों अविश्वास प्रस्ताव के प्रारूप को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि ये ऐसे ही सामने नहीं आया। सिद्धार्थनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य नौगढ़ प्रियंका सिंह की ओर से उप क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 का धारा 15 के तहत ब्लॉक प्रमुख रेनु मिश्रा के खिलाफ खुद और 54 सदस्यों का शपथ पत्र युक्त अविश्वास प्रस्ताव का प्रत्यावेदन दिया गया था। इसके खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेश श्रीवास्तव ने अगले दिन ही शपथ पत्र देकर बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में उनकी ओर से कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। इसके अलावा नौगढ़ ब्लॉक प्रमुख ने भी सात जिला पंचायत सदस्यों से नोटरी शपथपत्र दाखिल कर बताया कि इन सातों सदस्यों की तरफ से भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पर सहमति या शपथ पत्र नहीं दिया गया था। डीएम ने जिला शासकीय अधिवक्ता को जांच सौंपी। इसमें सामने आया कि कुछ सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर हस्ताक्षर तो किया, लेकिन इस संबंध में किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया। इसके अलावा कई सदस्यों के शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे। वहीं, शपथ पत्र के संबंध में नोटरी अधिवक्ता के रजिस्टर में सदस्यों के अंगूठे के निशान भी नहीं पाए गए। इसके अलावा अन्य बिंदुओं के आधार पर डीएम की तरफ से प्रियंका सिंह व 54 अन्य की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को कूटरचित व छलपूर्वक तैयार किया माना गया। इसी आधार पर डीएम ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रत्यावेदन को अस्वीकार कर दिया था। **संतकबीरनगर में अस्वीकार किया तो चले गए थे हाईकोर्ट** संतकबीरनगर में क्षेत्र पंचायत सदस्य संगीता देवी, मनीष कुमार, बदरुन्निशा व हाजरा खातून की तरफ से डीएम के पास ब्लॉक प्रमुख सेमरियावां के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रत्यावेदन दिया गया। सूत्रों ने बताया कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ चार सदस्यों के हस्ताक्षर थे। बाकी सबने अलग-अलग हस्ताक्षर किए थे। जबकि, नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या बल कुल सदस्यों का आधा होना जरूरी है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव देते समय इनमें से किसी एक सदस्य को डीएम के सामने पेश होकर सभी के संयुक्त हस्ताक्षर वाले प्रत्यावेदन को देना होता है, लेकिन सेमरियावां ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को डाक द्वारा कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। ऐसे में 27 जुलाई को इस अविश्वास प्रस्ताव के प्रत्यावेदन के मामले में डीएम की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके खिलाफ चारों सदस्य उच्च न्यायालय चले गए थे। न्यायालय की तरफ से डीएम के अस्वीकार किए गए फैसेले को सही ठहराते हुए रिट को खारिज कर दिया गया। **कहीं भारीभरकम बजट तो वजह नहीं** सूत्रों ने बताया कि जिले स्तर पर आए विकास के रूपों पर गलत मंशा रखे लोगों की नजर है। लगभग सभी ब्लॉक पर वर्तमान में 15वें वित्त के तहत शासन की तरफ से करोड़ों रुपये आए हैं। इसमें इन दोनों ब्लॉक में भी मोटी रकम है। सूत्रों ने दावा किया कि विकास की जगह इन ब्लाकों पर गलत नीयत के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने का खेल चल रहा है। सिद्धार्थनगर में तो केंस तक दर्ज हो गया। मंशा है कि पुराने ब्लॉक प्रमुखों की जगह अपने चहेते ब्लॉक प्रमुखों को वहां स्थापित कर दिया जाए। इससे विकास के साथ अपने विकास की योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसी मंशा के खिलाफ लोकसभा चुनाव के बाद क्षेत्र पंचायतों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने का खेल शुरू हो गया है। डीएम सिद्धार्थनगर डॉ. राजा गणपति आर ने बताया कि नौगढ़ ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ बीडीसी प्रियंका सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ बीडीसी के हस्ताक्षर फर्जी होने के मामले में प्रियंका सिंह के खिलाफ केंस दर्ज कराया गया है।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों के पार्टी कार्यालयों में झंडारोहण का कार्यक्रम समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी देने के साथ सभी देशवासियों को बधाई दी गई। अमर शहीदों के सपनों को पूरा करने का संकल्प भी लिया गया।



फर्श पर पड़ा खून धोया... लाश को भी किया साफ



सिर पर बांधी पगड़ी... बाइक पर रखी लाश

दो भाइयों ने मालिक का कत्ल कर 20 किमी दूरी तय कर ठिकाने लगाया शव

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ के आलमबाग इलाके में किरायेदार भाइयों ने बुजुर्ग मकान मालिक की हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। बुजुर्ग मकान खाली करवाकर दूसरे को देने की तैयारी में थे। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। लखनऊ के आलमबाग के रामनगर में किरायेदार दो सगे भाइयों ने एक वृद्ध मकान मालिक व कारोबारी की हत्या कर दी। इसके बाद शव शारदा नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला कि वृद्ध उनसे मकान खाली करवाने की तैयारी में थे। इसे लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद दोनों ने वारदात अंजाम दे डाली। पुलिस गोताखोरों की मदद से नहर में शव की तलाश करवा रही है। आशियाना के एलिडको उद्यान निवासी वीरेंद्र नरुला (70) के दोनों बेटे सिद्धार्थ व गौरव अलग-अलग शहरों में रहकर नौकरी करते हैं। उनका पुराना मकान आलमबाग के रामनगर इलाके में है, वहां पर एक परिवार किराये पर रहता है। 11 अगस्त को दोपहर वीरेंद्र ने पत्नी अमला से कहा था कि वह किराया लेने बाइक से जा रहे हैं। फिर वह नहीं लौटे। सोमवार को मामले में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने किरायेदार सुखविंदर उर्फ विकी व उसके भाई अजीत को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उन्होंने स्वीकारा कि दोनों ने वीरेंद्र की हत्या कर शव गोसाईगंज में शारदा नहर में फेंक दिया। सुखविंदर प्रॉपर्टी डीलर हैं, जबकि अजीत सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करता है।

एक आरोपी ने बाइक चलाई और दूसरा शव को पकड़े रहा। करीब 20 किमी की दूरी तय कर देर रात गोसाईगंज पहुंचे और नहर में शव फेंककर लौट आए। इस दौरान कहीं पर पुलिस ने उनको नहीं रोका। ऐसे में रात के वक्त पुलिस की सक्रियता पर भी सवालिया निशान लगा है। **घर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज कर दिए डिलीट**
वीरेंद्र के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। पुलिस ने जब कैमरे खंगाले तो पता चला कि फुटेज डिलीट कर दिए गए। इस बारे में आरोपियों ने बताया कि उनको पता था कि सीसीटीवी अहम सुबूत है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। सीसीपी ने बताया कि जांच के दौरान वीरेंद्र के पुराने घर के पास लगे कैमरे खंगाले। इसमें दिखा कि वीरेंद्र व एक अन्य शख्स एक साथ घर जाते हैं। फिर दोनों बाहर जाते दिखे। कुछ देर बाद वीरेंद्र दोबारा घर की ओर जाते नजर आए। लेकिन, नहीं लौटे। यहीं से शक गहराया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वारदात में कोई और भी शामिल है या नहीं। इसको लेकर भी पड़ताल जारी है। **किसी और की भूमिका है या नहीं...जांच जारी**
सीसीपी पूर्वी ने बताया कि मामले में आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ की जा रही है। वारदात में कोई और भी शामिल है या नहीं, इसको लेकर भी पड़ताल जारी है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

दो साल से नहीं दिया था किराया
पुलिस की जांच में सामने आया कि 14 साल से सुखविंदर का परिवार किराये पर रहता है। उसके पिता हरबंश नशे के लती हैं। मां कहीं बाहर गई थीं। 11 अगस्त को दोनों भाई ही घर पर थे। करीब दो बजे दोपहर को वीरेंद्र एक ब्रोकर को लेकर वहां पहुंचे थे। मकान देखकर ब्रोकर चला गया था। वीरेंद्र फिर घर गए। तब सुखविंदर व अजीत उनसे झगड़ने लगे। दो साल से किराया न देने की वजह से वीरेंद्र मकान खाली करवाकर दूसरे को देने की तैयारी में थे। इसी बात पर विवाद और फिर मारपीट हुई। तभी उनकी हत्या कर दी। **सिर पर पगड़ी बांधी, बाइक पर बीच में रखा शव, 20 किमी दूरी तय कर ठिकाने लगाया**
सीसीपी पूर्वी शशांक सिंह के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 11 अगस्त की दोपहर करीब तीन बजे वीरेंद्र की हत्या की। इससे पहले मारपीट के दौरान उनको दीवार से लड़ा दिया। करीब दो घंटे तक बेहोश रहने के बाद उनकी सांसें थम गईं। वीरेंद्र नरुला की हत्या कर तकरीबन 12 घंटे तक शव घर में रखे रहे। समझ नहीं पा रहे थे कि शव कैसे और कहां ठिकाने लगाएं। इस दौरान फर्श पर फैला खून धुला। पगड़ी बांधने से पहले शव को भी अच्छे से साफ किया। फिर साजिश रची। वीरेंद्र के शव के सिर पर पगड़ी बांधी। बाइक में शव को बीच इस तरह से रखा, जैसे कोई बैठा हुआ है।

गोंडा में दो स्कूल बसों में भिड़ंत

चालक समेत दस छात्र घायल, हादसे से सहमे छात्र

लखनऊ, संवाददाता। गोंडा जिले में दो स्कूल बसों में भिड़ंत हो जाने से 10 छात्र घायल हो गए। बच्चे स्कूल ले जाए जा रहे थे। हादसे के समय एक बस में करीब 35 तो दूसरी बस में 50 छात्र सवार थे। गोंडा जिले की करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ हाइवे पर नकहा बसंत मोड़ पर दो स्कूल बसों में भिड़ंत हो गई। सुबह करीब सात बजे हुई दुर्घटना में चालक समेत दस छात्र घायल हुए। शुक्र रहा कि दोनों बसों में आपस में भिड़ने के बाद हाइवे के डिवाइडर पर चढ़ गई जिससे सड़क किनारे खाई में पलटने से बच गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया।



सीएम योगी ने बनाया नया रिकार्ड

आठवल् बार ध्वजारोहण करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने, तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव

2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला
स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी बने

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन पर ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वह विधान भवन पर सबसे अधिक लगातार आठवल् बार ध्वजारोहण करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके साथ योगी स्वतंत्रता के पश्चात सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उनके दोनों कार्यकाल मिलाकर सात वर्ष 148 दिन हो चुके हैं।



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विधान भवन पर ध्वजारोहण कर एक नया कीर्तिमान बना दिया। वह विधान भवन पर सबसे अधिक लगातार आठवल् बार ध्वजारोहण करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।

सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी बने

योगी 19 मार्च 2017 को पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उनका पहला कार्यकाल 12 मार्च 2022 को समाप्त हुआ था। वर्ष 2022 के चुनाव में भी भाजपा को बहुमत मिलने पर योगी ने 25 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने लगातार आठवल् बार ध्वजारोहण का कीर्तिमान तो बनाया ही, स्वतंत्रता के

पश्चात सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। दोनों कार्यकाल मिलाकर सात वर्ष, 148 दिन हो गए।

मायावती ने भी किया है आठ बार ध्वजारोहण

पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का कार्यकाल चार बार में सात वर्ष, 16 दिन का था। मायावती ने अपने चार बार के कार्यकाल में आठ बार ध्वजारोहण किया है। तीन बार मुख्यमंत्री बने मुलायम सिंह यादव का कुल कार्यकाल छह वर्ष, 274 दिन का रहा था। दो बार मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद का कार्यकाल पांच वर्ष, 345 दिन और अखिलेश यादव एक बार के कार्यकाल में पांच वर्ष, चार दिन मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्रता के पूर्व गोविंद वल्लभ पंत का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे अधिक आठ वर्ष, 127 दिन का रहा था।

दो पक्षों में वर्चस्व को लेकर मारपीट-पथराव के बाद फायरिंग

यूपी के कानपुर में गुरुवार शाम वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट पथराव के बाद फायरिंग हो गई। बवाल की सूचना पर पुलिस आरोपियों के घर दबिश देने गई तो पड़ोस में रहने वाले वृद्ध को अटैक पड़ने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था लेकिन फायरिंग की बात गलत है।

संवाददाता, कानपुर। चक्रे की लाल बंगला बाजार में गुरुवार शाम वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में मारपीट पथराव के बाद फायरिंग हो गई। बवाल की सूचना पर पुलिस आरोपियों के घर दबिश देने गई तो पड़ोस में रहने वाले वृद्ध की अटैक पड़ने से मौत हो गई। इस दौरान किसी ने अफवाह फैला दी कि फायरिंग के दौरान गोली लगने से वृद्ध की मौत हुई है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन फायरिंग की बात गलत है। सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सफीपुर प्रथम निवासी विकास यादव ने बताया कि गुरुवार शाम वह बाइक से रक्तदान करने जा रहा था। खटिकाना निवासी मुन्ना मुस्लिम ने अपने चार पांच साथियों के साथ गली-गलौज करते हुए पथराव कर दिया और तमंचे से हवाई फायरिंग भी की। घटना से इलाके में अफरातफरी मच गई शोर सुनकर लोग दौड़े तो आरोपित धमकाते हुए भाग निकले। बवाल की सूचना पर चक्रे पुलिस दबिश देने पहुंची तो इलाके में रहने वाले 60 वर्षीय अशोक कश्यप की अटैक पड़ने से मौत हो गई। इस दौरान अफवाह फैला दी गई कि फायरिंग के दौरान गोली लगने से अशोक की मौत हुई है। हालांकि, मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अशोक नशे के लती थे और उनको टीबी की बीमारी थी।

भोजन नली में फंसा टूथब्रश का टुकड़ा

डाक्टरों ने सर्जरी कर बचाई 23 साल के युवक की जान



संवाददाता, कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में बुधवार को सर्जन प्रो. आरके जौहरी और उनकी टीम ने जटिल सर्जरी कर डाउन सिंड्रोम से ग्रसित युवक का जीवन सुरक्षित किया। 23 वर्षीय युवक ने करीब 10 दिन पहले ब्रश को चबाकर निगल लिया था। ब्रश का टुकड़ा भोजन नली के जरिए आमाशय तक पहुंच गया था। विशेषज्ञों ने इंडोस्कोपी की मदद से गले के रास्ते जाकर भोजन नली के निचले भाग में फंसे ब्रश को टुकड़े को निकाला।

पेट में दर्द की शिकायत लेकर आया था युवक
प्रो. आरके जौहरी ने बताया कि ओपीडी में पेट दर्द की शिकायत लेकर आए मरीज के एक्सरे में पेट में कुछ फंसा दिखा। सीटी स्कैन की मदद से ब्रश के टुकड़े की स्थिति पता चली। जिसके बाद इंडोस्कोपी की मदद से ब्रश के टुकड़े को गले तक लाया गया, जहां से उसे शरीर के किसी अंग को नुकसान पहुंचाए बिना निकाल लिया गया। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रो. संजय काला ने सर्जरी विभाग की टीम की सराहना की।

सिपाही भर्ती परीक्षा अपने साथ ये सामान न लाएं अभ्यर्थी



सिपाही भर्ती परीक्षा में नया अपडेट... आवेदन में आधार नंबर नहीं तो दो घंटे पहले करें ये काम

लखनऊ, संवाददाता। सिपाही सीधी भर्ती की दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में अपने आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया है, उन्हें अनिवार्य रूप से दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर जाकर आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा। अन्य अभ्यर्थियों को भी इसी तरह दो घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचने का निर्देश दिया गया है। परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पूर्व किसी को भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है। उम्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्णा ने बताया कि अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए उनके परीक्षा केंद्रों वाले जिलों की सूची शुक्रवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से तीन दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बता दें कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को रोजाना दो पालियों में होगी।

फरवरी में हुई परीक्षा के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए थे, जिन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सॉल्वरों पर नकेल कसने के लिए बोर्ड तकनीक का इस्तेमाल करेगा। दूसरे की जगह परीक्षा देने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी होगी।

लड़कियों के परीक्षा केंद्र पड़ोसी जिले में

डीजी ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले के पड़ोसी जिले में आवंटित किए गए हैं। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे मंडल में बनाया गया है। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के मुताबिक जिला स्तरीय समितियों ने किया है। जिन 8 जिलों में केवल पांच परीक्षा केंद्रों को ही चुना गया था, वहां केंद्र नहीं बनाए गए हैं। शेष 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी।

इन पर रहेगा प्रतिबंध

परीक्षा केंद्र पर पाठ्य सामग्री, कागज के टुकड़े, ज्यामितीय-पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबिल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, मोबाइल, चाभी, कैमरा, घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वाच, ब्लूटूथ डिवाइस, इयरफोन, माइक्रो फोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाना, सिगरेट, लाइट, माचिस, गुटका आदि ले जाने पर प्रतिबंध है। अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

हेल्प लाइन नंबर जारी

बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प लाइन नंबर 8867786192 और 9773790762 जारी किया है।



राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

रक्षाबंधन पर रहेगा भद्रा का साया दोपहर 1:33 बजे के बाद बांधें राखी

लखनऊ, संवाददाता। रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त की विशेष ध्यान रखें। तौं दंडकींद 2024: भाई-बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन 19 अगस्त को सावन की पूर्णिमा पर मनाया जाएगा। इस बार भद्रा का साया होने के कारण दोपहर 1:33 के बाद बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद मिश्र ने बताया कि 19 अगस्त को सुबह 3:05 पर पूर्णिमा शुरू हो रही है। इसके साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा रात्रि 11:55 तक रहेगी। भद्रा सोमवार को दोपहर 1:33 तक रहेगी। इसलिए भद्रा के बाद राखी बांधना शास्त्र सम्मत बताया गया है। इसके अलावा सोमवार को सुबह 7:32 से 9:09 तक राहुकाल रहेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य न करें। रक्षाबंधन के लिए लोगों में उत्साह है। बाजारों में राखी की खरीदारी की जा रही है। मिष्ठान भंडार, कपड़ों के शोरूम, उपहार की दुकानों व ज्वेलर्स के शोरूमों पर भी लोगों की भीड़ पहुंच रही है। ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन में खरीदारी खूब की जा रही है।

ज्योतिषाचार्य पं. वेदप्रकाश प्रवेता ने बताते हैं कि इस बार राखी पर चार योग बन रहे हैं, जो कि बहुत ही उत्तम हैं। सूर्य में शुक्र होने के कारण सुबह से लेकर शाम तक शुक्रादित्य योग रहेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि एवं शोभन योग, रवि योग व सौभाग्य योग में रक्षाबंधन मनेगा। ये सभी योग पूरे दिन रहेंगे।

राखी बांधने की सही विधि

बहनों को भाई की कलाई पर राखी सही विधि से बांधनी चाहिए। इसके अनुसार, सबसे पहले भाई को रोली, अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद भाई की दाहिने कलाई पर राखी बांधें। उसे मिटाई खिलाएं। फिर भाई की आरती उतारें और उसके सुखी जीवन की कामना करें। वहीं राखी बंधवाने के बाद भाई को अपनी बहनों के चरण स्पर्श करने चाहिए। इसके साथ ही रक्षा बंधन का मंत्र (येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वाम् प्रतिबद्धनामि ,रक्षे माचल माचलः।) भी बोलना चाहिए।

बुआ की गिरफ्तारी से सामने आएगा सच



भतीजी संग घटना होने पर भी नवाब के साथ बेफिक्र क्यों बैठी थी महिला

कन्नौज, संवाददाता। अपनी सगी भतीजी को लेकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज लेकर पहुंची उसकी बुआ अब पुलिस के निशाने पर है। हैरानी यह है कि घटना के बाद के दो दिनों तक खुलेआम घूमने वाली वह महिला पिछले तीन दिनों से लापता हो गई है। उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। पुलिस को अब तक बुआ का कोई सुराग नहीं मिला है।

भतीजी के साथ हुई वारदात में बुआ की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। उसकी मौके पर मौजूदगी और उसके बाद पहले शिकायत में शामिल होना और बाद में मुकदमे पर सवाल उठने शुरू हो गए थे।

रविवार रात हुई वारदात के बाद सोमवार और मंगलवार को वह जिला अस्पताल से लेकर कचहरी तक मंडराती रही। दोनों ही दिन मीडिया के सामने इस पूरी घटना को गलत बताकर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाती रही। इस बीच मंगलवार को जब किशोरी के माता-पिता यहां पहुंचे और उन्होंने बुआ की भूमिका पर ही सवाल करते हुए उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो वह लापता हो गई।

हालांकि बताया जा रहा है कि मंगलवार को वह जिला अस्पताल में मीडिया को अपना बयान देने के बाद कचहरी पहुंची थी।

उसके बाद वह वहां से कहां लापता हुई, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ सकी है। मुकदमे में उसका भी नाम शामिल करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी

है। पुलिस की अलग-अलग छह टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। अब तक कामयाबी नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट में उसका नाम शामिल करने के बाद 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वह पुलिस की आंख में धूल झाँककर गायब हो गई है। पुलिस उसकी सरगमीं से तलाश कर रही है।

बुआ की गिरफ्तारी से सामने आएंगे कई अहम राज

जानकार बता रहे हैं कि पहले ही दिन से अपनी संदिग्ध भूमिका की वजह कर लोगों की निगाह में आई किशोरी की बुआ की गिरफ्तारी से कई अहम राज सामने आ सकते हैं। वह आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के कॉलेज में किन हालातों में पहुंची।

उसे बुलाया गया था, यह वह खुद ही वहां गई थी। अपनी भतीजी को लेकर वहां क्यों पहुंची। अगर उसकी भतीजी के साथ वहां घटना हुई थी तो वह आरोपी के साथ बेफिक्र होकर क्यों बैठी थी, जैसा कि वायरल वीडियो में दिख रहा है। शुरु में आरोप लगाने के बाद वह अपने बयान से क्यों पलटी। आखिर वह भागी क्यों।

क्या उसके बैंक खाते में किसी ने इस प्रकरण में अपना बदलने के लिए रकम डाली थी। इस तरह के कई सवाल हैं जो उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में सामने ला सकती है।

एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि पुलिस की टीम फिलहाल उसकी तलाश में लगी है। हर संभावित ठिकानों पर उसकी तलाश की जा रही है।

काशी का अनोखा गांव

जहां तीन से 19 वर्ष की उम्र 12 साल पहले यहां 75 लड़कियां खेल लड़कों से ज्यादा के 300 फुटबाल खिलाड़ी जुआ खेलते थे बच्चे चुकी हैं नेशनल हैं लड़कियां



बनारस में बसा छोटा सा ब्राजील: जहां रहते हैं तीन से 19 साल की उम्र के 300 फुटबाल खिलाड़ी, लड़कियां ज्यादा

वाराणसी, संवाददाता। काशी का अनोखा गांव है पहाड़ी। इस गांव में 1500 परिवारों में 300 फुटबाल खिलाड़ी हैं। जहां 12 साल पहले बच्चे जुआ खेलते थे वहां अब हर शाम जब वे ग्राउंड पर खेलने के लिए निकलते हैं, तो रौनक किसी खेल गांव जैसी लगती है। बनारस में एक छोटा-सा ब्राजील बसा है। गांव का नाम है पहाड़ी। और यहां रहने वाले 1500 परिवारों के 300 बच्चे फुटबाल खेलते हैं। खूबसूरत बात यह है कि इनमें लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। बार-बार सिलवाए हुए जूते पहनकर हर शाम जब वे ग्राउंड के लिए निकलती हैं, तो रौनक किसी खेल गांव जैसी लगती है।

इस गांव के बच्चे 12 वर्ष पहले तक जुआ खेलते थे। इधर-उधर भटकते थे। तभी पास की कॉलोनी में रहने वाले फुटबाल खिलाड़ी भैरव दत्त इन बच्चों के लिए 3-4 फुटबाल ले आए। मैदान के झाड़-झंखाड़ और गड्डे ठीक करवाकर फुटबाल खेलने लायक बना लिया। फिर गोल पोस्ट के नाम पर एक तरफ बांस के पोल लगाए और दूसरी तरफ कुर्सी रख दी। शुरुआत में सिर्फ सात-आठ बच्चे आते थे। उनके लिए कोच भैरव ने किस्तों में किट मंगवाई। यहां-वहां से जूतों के पैसे जुटाए। तीन नेशनल खेल चुकी सृष्टि कहती हैं कि उन्हें पहली किट भैरव सर ने ही दिलवाई थी। वह दूसरों को देखने मैदान पर जाती थी और सोचती थी कि खेल पाऊंगी या नहीं। फुटबाल की इस पीढ़ी को तैयार करते हुए कोच भैरव को 40 साल हो चुके हैं। इस मैदान पर पांच साल की, जो बच्ची खेलने आती थी, अब वह 17 साल की है।

पिथौरागढ़ के भैरव सर जैसे तो बरेका में नौकरी करने काशी आए थे। अब उनके सिखाए बच्चे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। यही नहीं, अपने खेल के बूते खेल कोटे से नौकरी कर रहे हैं और स्कॉलरशिप पर पढ़ाई भी। एमफिल, बीएड और पीएचडी तक। फिलहाल सात लड़कियां बीएचयू और दो गुवाहाटी से रिसर्च कर रही हैं। तीन प्रोफेसर बन गई हैं। सात पंजाब में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप की एक शर्त है। पढ़ाई के बदले इन सभी को पदक जीतने होते हैं। कुछ बेटियां ओडिशा व पश्चिम बंगाल के फुटबाल क्लब का हिस्सा हैं।

75 लड़कियां नेशनल खेल चुकी हैं। इनमें लखपति के परिवार के आठ बच्चे हैं। गांव के लोग इस परिवार को लखपति बुलाते हैं, लेकिन गांव में सबसे टूटा-फूटा घर इनका ही है। हां, उनके हिस्से इस गांव के सबसे ज्यादा मेडल जरूर हैं। पार्वती के परिवार में छह बहनें हैं। तीन बहनें फुटबॉलर हैं और दो नेशनल खेल चुकी हैं। जिस ग्राउंड पर इन बच्चों ने सबसे पहले खेलना शुरू किया, वहां अब इमारत बन गई है। जिस गांव में 300 खिलाड़ी हैं, वहां अब मैदान नहीं। खेलने के लिए अब डेढ़ किलोमीटर दूर बरेका जाना होता है।



क्या तैयार हैं हम?

• 2036 तक जनसंख्या
152.2 करोड़
तक पहुंचने की उम्मीद.

• कामकाजी लोगों की संख्या बढ़कर
65%
हो जाएगी.

• महिलाओं की आबादी
0.3% बढ़कर
48.8%
हो जाएगी

• **15 साल**
से कम आयु के लोगों का अनुपात घटेगा.

• 2036 तक
1000 पुरुषों पर
952
महिलाएँ होने की उम्मीद.

• **60 साल**
और उससे ज्यादा की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि.

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने रिपोर्ट में जारी की है, जिसमें बताया गया है कि साल 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।



मुझे विश्वास है कि पेरिस ओलंपिक भारतीय स्पोर्ट्स की उड़ान के लिए एक लॉन्च पैड साबित होने वाला है। ये टर्निंग पॉइंट है हमारा। इसके बाद विजय ही विजय है। हम अब रुकने वाले नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

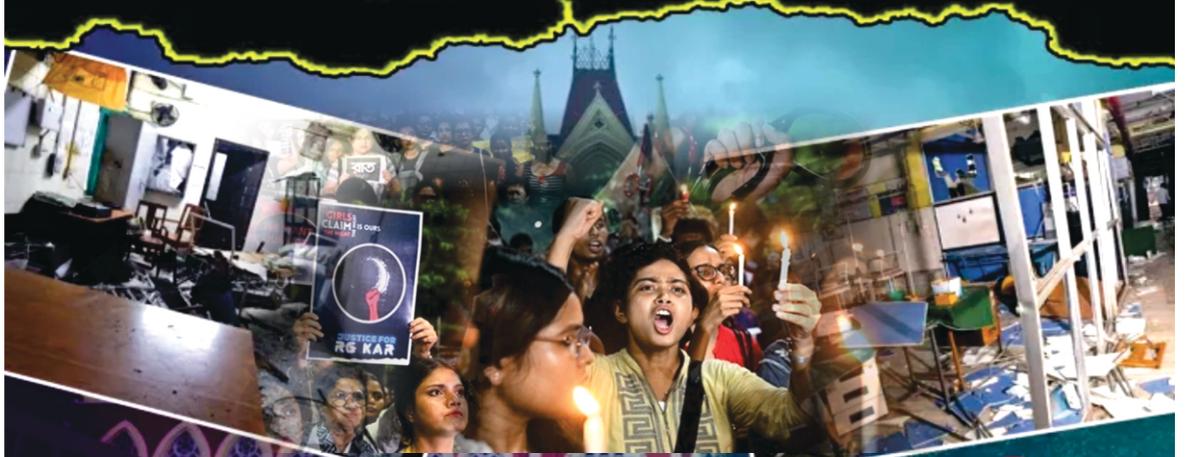
पेरिस ओलंपिक में छह पदक जीतने के बाद भारतीय एथलीट्स देश लौट चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीय एथलीट्स लाल किले पर हुए कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। इसके बाद सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की।

अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने किया नमन

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राष्ट्र के प्रति किए गए उनके योगदान को याद किया और उन्हें नमन किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी। लगभग 6 दशक एक निष्कलंक जीवन जीते हुए वे भारतीय राजनीति को नई ऊंचाइयों पर ले गए। भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उनके सद्प्रयासों के प्रति यह राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा।



कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार



'अस्पताल बंद करना ही बेहतर, राज्य की मशीनरी नाकाम', मेडिकल कालेज में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता HC की सख्त टिप्पणी

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस घटना पर लचता जताते हुए राज्य मशीनरी को पूरी तरह नाकाम बताया है। वहीं कोर्ट ने सलाह दी है कि बेहतर होगा अस्पताल बंद किया जाए। वहल अस्पताल में मौजूद मरीजों को किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। बता दें कि आरजी कर अस्पताल के नजदीक पुलिस बैरिकेड तोड़कर भीड़ परिसर में घुस गई थी। कुछ लोगों ने कुर्सियां और बोर्ड तोड़ दिए थे। यह घटना तब हुई जब जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं कोलकाता की सड़कों प्रदर्शन कर रही थीं। पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ होती रही अस्पताल में हुई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस ने

जानकारी दी थी कि 30-40 युवक ने अंदर घुसकर तोड़फोड़ की है। तोड़फोड़ करने वाले ये लोग कौन है इसका पता नहीं चल सका है। बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ होती रही। इस पर अब प्रश्न यह उठने लगा है कि क्या महिलाओं के शांतिपूर्ण आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए तो यह सुनियोजित घटना नहीं है। साथ ही भीड़ ने धरना मंच भी तोड़ दिया।

कई अस्पतालों में आज भी जारी है डाक्टरों की हड़ताल बताते चलें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में रेजिडेंट डाक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। इस वजह से शुक्रवार को भी एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जीबी पंत सहित दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर ओपीडी, नियमित सर्जरी व अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएँ प्रभावित रहेंगी।



नवाब सिंह ने किया था दुष्कर्म!

नवाब सिंह का होगा डीएनए टेस्ट!...

कन्नौज। कन्नौज कांड में नया अपडेट सामने आया है। पुलिस दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि के लिए आरोपी नवाब सिंह का डीएनए जांच कराएगी। एसपी ने डीएनए की जांच की मंजूरी के लिए मांग की है। उधर, 12 अगस्त को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेजे जाने के बाद आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी, उस पर 14 अगस्त को सुनवाई हुई। आरोपी की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। आपको बता दें कि नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। शुरुआती मेडिकल टेस्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दुष्कर्म की बात कही थी। इसी बयान के आधार पर आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म की भी धारा बढ़ाई गई है। इसके साथ ही पुलिस की छह टीम उसकी बुआ की

तलाश में जुटी हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, कन्नौज मामले में लड़की की मेडिकल जांच से पता चला है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। कन्नौज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अमित कुमार आनंद ने कहा कि लड़की ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में भी दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दुष्कर्म की पुष्टि के साथ, आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 (बलात्कार) की धाराएं बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त आरोपों के साथ कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। एसपी ने कहा कि लड़की की बुआ, जो कथित तौर पर नाबालिग को नवाब सिंह यादव के पास लेकर आई थी, उसे बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह मंगलवार को पुलिस के सामने पेश नहीं हुई।

इस वजह से

सपा ने नवाब से बनाई थी दूरी



इस बार नवाब पर कसा शिकंजा

15 मुकदमों में पुलिस न रख सकी थी हाथ...

कन्नौज। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव का मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नाबालिग ने दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह पर पहले 15 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की थी। इस बार नवाब के खिलाफ 16वां मुकदमा दर्ज हुआ तो उस पर शिकंजा कसा गया। एक समय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का करीबी था, लेकिन 2017 के बाद सपा ने उससे दूरी बना ली थी। कहा तो ये भी जाता है कि नवाब सिंह ने अखिलेश यादव के साथ दगाबाजी की थी। दरअसल, नवाब सिंह यादव का यह सियासी रसूख ही था कि उसके खिलाफ अलग-अलग समय पर कुल 15 मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कभी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। यह मुकदमे बसपा, भाजपा, सपा शासन में लगते रहे। भाजपा की पिछली सरकार में भी मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार चूकि मामला एक नाबालिग की असमत से जुड़ा था, तो पुलिस ने कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं दिखाई। अब उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। आगे और भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

2017 के बाद सपा से बनने लगी थी दूरी, घटने लगा था कद

सपा शासन के दौरान सत्ता के गलियारों में अपनी धमक रखने वाले नवाब सिंह के पार्टी से मतभेद भी शुरू हुए। इसकी शुरुआत हुई वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान। कहा जाता है कि तब नवाब सिंह यादव ने निर्वा विधानसभा सीट से टिकट की मांग की। पार्टी ने मांग नहीं मानी। इससे खेमेबंदी शुरू हो गई। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव यहां से चुनाव हारीं तो नवाब सिंह यादव पर दगाबाजी का आरोप लगा। तब सपा ने पूरी तरह से दूरी बना ली थी। कभी पार्टी की बागडोर संभालने वाले नवाब सिंह को पार्टी के ही कार्यक्रम की जिम्मेदारी से दूर किया जाने लगा। इसके बावजूद नवाब सिंह यादव पार्टी का झंडा उठाकर जनहित के मुद्दे पर धरना-प्रदर्शन करता रहा। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब खुद अखिलेश यादव ने यहां से दावेदारी की तो नवाब सिंह यादव ने उनके लिए प्रचार किया था। फिर चर्चा शुरू हुई कि दोनों के बीच नजदीकी बढ़ रही है।



'काका' ने ठुकराया था बिग बास का करोड़ों का आफर

राजेश खन्ना को मिला था बिग बास का आफर बिग बास में बुलाने के लिए एक्टर को पेश की गई मोटी रकम बिना सोचे समझे ही राजेश ने कर दिया था मना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बास की फैन फॉलोइंग काफी अधिक है। दर्शक छोटे पर्दे से लेकर ओटीटी तक इसे देखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार इस विवादित शो के लिए इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी अप्रोच किया गया था। बिग बास के मेकर्स की तरफ से राजेश को मोटी रकम भी ऑफर हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था और बिग बास को न करने को लिए साफ इनकार कर दिया था। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं।

राजेश खन्ना ने बिग बास के लिए किया था मना

साल 2012 में राजेश खन्ना ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन उनसे जुड़े किस्से आए दिन चर्चा का विषय बनते रहते हैं। ई टाइम्स की खबर के अनुसार पत्रकार पीटर जॉन ने रेडिफ को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि राजेश खन्ना को बिग बास का ऑफर मिला था, उन्होंने बताया था—

बिग बास के मेकर्स ने इस शो की शुरुआत में राजेश खन्ना को बुलाने का प्लान बनाया। चूंकि वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर थे और मेकर्स इसका फायदा उठाना चाहते थे। बिग बास निर्माताओं ने उन्हें एक एपिसोड के लिए 3.5 करोड़ की मोटी रकम भी ऑफर की थी। लेकिन राजेश खन्ना ने इसे लिए मना कर दिया और कहा था कि राजेश खन्ना ऐसे शो थोड़े न करेगा।

बता दें पीटर जॉन भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन राजेश खन्ना और बिग बास के मसले को उन्होंने सबके सामने रहकर इंडस्ट्री में सनसनी मची दी थी।

राजेश खन्ना ने बदल दिया था मना

पीटर जॉन ने बाद में ये भी बताया था कि कुछ समय के बाद राजेश खन्ना ने अपना फैसला बदलने का विचार किया और वह बिग बास में जाने का मन बना रहे थे। लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी और मेकर्स ने उनमें दिलचस्पी दिखाया बंद कर दिया था।

राजेश खन्ना हिन्दी सिनेमा के पहले सुपरस्टार थे। 80 के दशक में अभिनेता की फिल्मों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और अपार सफलता हासिल की। लेकिन करियर के अंतिम पड़ाव पर उनको सलमान खान के पापुलर रियलिटी शो बिग बास का आफर मिला था। जिसे बिना सोचे समझे राजेश खन्ना ने ठुकराया दिया था। आइए मामले को डिटेल में जानते हैं।



15 अगस्त को रिलीज हुई खेल खेल में अक्षय कुमार संग नजर आए कई स्टार्स प्रज्ञा जायसवाल ने खींचा लोगों का ध्यान

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में कई फिल्मों ने एक साथ दस्तक दी। इसमें श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 जॉन की वेदा और अक्षय कुमार की खेल खेल में भी शामिल रही। अक्षय-तापसी की फिल्म को लोगों ने मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके साथ ही इस फिल्म में नजर आई प्रज्ञा जायसवाल ने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, एमी विर्क स्टारर फिल्म 'खेल खेल में' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इन स्टार्स के अलावा वाणी कपूर, आदित्य सील, प्रज्ञा जायसवाल, फरदीन खान भी लीड रोल में दिखाई दिए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है।

तापसी और वाणी के अलावा फिल्म 'खेल खेल में' में प्रज्ञा जायसवाल ने भी नैना का किरदार निभा कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे में अब फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर ये प्रज्ञा जायसवाल है कौन। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

साउथ की एक्ट्रेस हैं प्रज्ञा

एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल साउथ का एक जाना-माना नाम है। उन्होंने तेलुगु की कई फिल्मों में काम कर फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई है। एक्ट्रेस ने साल 2014 में तमिल फिल्म 'विराडू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने नन्दमुरी बालकृष्ण के साथ 'अखंड', वरुण तेज के साथ 'कांचे' और 'जय जानकी नायक', 'गुट्टोडु', 'नक्षत्रं' समेत कई फिल्मों में बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। वहीं, उन्होंने हिंदी फिल्म 'टीटू एमबीए' में भी काम किया, जिसमें उनके साथ निशांत दाहिया लीड रोल में दिखाई दिए थे। हालांकि, यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब वह 'खेल खेल में' नजर आई हैं, ऐसे में देखना होगा कि लोग उन्हें इस फिल्म में कितना पसंद करते हैं।

बेहद खूबसूरत हैं प्रज्ञा जायसवाल

36 साल की प्रज्ञा जायसवाल रियल लाइफ में भी बहुत खूबसूरत हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और वहां अपनी हॉट फोटोज शेयर करती रहती हैं। एक्ट्रेस की इन फोटोज में देखा जा सकता है कि वह अपने किलर लुक से फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम कर रही हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रज्ञा हॉटनेस के मामले में दिशा पाटनी हो या कोई अन्य टाउन एक्ट्रेस किसी से कम नहीं हैं। इंस्टाग्राम पर देखा जा सकता है कि बिकिनी में हो या एथनिक लुक में एक्ट्रेस की तमाम फोटोज इंटरनेट पर तबाही मचाने के लिए काफी हैं।



साल 2014 में तमिल फिल्म 'विराडू' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने नन्दमुरी बालकृष्ण के साथ 'अखंड', वरुण तेज के साथ 'कांचे' और 'जय जानकी नायक', 'गुट्टोडु', 'नक्षत्रं' समेत कई फिल्मों में बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम किया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों सोना डे तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि, उनके वायरल होने के पीछे उनका कोई खास वीडियो या रील नहीं बल्कि एक एमएमएस वीडियो है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर सोना डे उस समय विवादों के घेरे में आ गईं, जब उनका एक कथित एमएमएस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यह वीडियो, जिसमें सोना कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रही हैं। हालांकि, इस वीडियो को सोना डे ने पूरी तरह से फेक बताया है और कहा है कि वीडियो में वह नहीं हैं। आइए जानते हैं, सोना डे आखिर हैं कौन और क्या करती हैं?

सोना डे एक लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल पर 2.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। सोना अपने यूट्यूब चैनल पर लगातार डांस वीडियो और व्लॉग अपलोड करती रहती हैं। इन दिनों सोना डे को इंटरनेट पर काफी सर्च किया जा रहा है क्योंकि उनका कथित एमएमएस वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

अपने कथित वायरल वीडियो पर सोना डे ने कहा, "यह मैं नहीं हूँ और यह वीडियो केवल मुझे बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक एडिट किया गया वीडियो है।" सोना ने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो जारी कर कहा कि यह वीडियो उनका नहीं है और वीडियो में दिख रही महिला बांग्लादेशी है और उनके नाम पर उस वीडियो को फेलाकर उन्हें बदनाम किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर वीडियो लीक होने के बाद से ही यूजर्स के बीच कई सवाल पैदा हो गए। कई लोगों ने कमेंट करते हुए पूछा, 'यह वाकई सोना डे की हरकत थी? या यह एआई से बनाया गया कोई डिजिटल हेरफेर है?' वीडियो को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल उठे और अटकलें लगाई जाने लगीं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए पूछा, 'क्या यह कोई डीपफेक वीडियो है?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'सोना डे का यह वीडियो वायरल होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि सोशल मीडिया पर आसानी से किसी को भी बदनाम किया जा सकता है।' एक और यूजर ने लिखा, 'सोना डे के साथ यह गलत हुआ है।'

कौन हैं सोना डे सुनखियों में आई सोशल मीडिया

इंफ्लुएंसर

श्वेता तिवारी की अपमानजनक शादी का पलक तिवारी पर कैसा पड़ा असर



एंटरटेनमेंट डेस्क। अभिनेत्री श्वेता तिवारी अपनी निजी जिंदगी को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। उनकी पहली शादी राजा चौधरी से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी पलक तिवारी हैं। उनकी शादी को महत्वपूर्ण मुद्दों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण 2007 में उनका तलाक हो गया। 2013 में, उन्होंने अभिनव कोहली से शादी की, और उनका एक बेटा रेयांश कोहली है। हालांकि, उनकी दूसरी शादी में भी मुश्किलें आईं और उन्होंने और अभिनव ने 2019 में अलग होने की घोषणा की। वहीं, अब श्वेता ने अपनी टूटी हुई शादी और इसका बेटी पलक की परवरिश पर पड़े असर को साझा किया है।

श्वेता तिवारी ने हाल ही में बताया कि कैसे वह अपनी अपमानजनक शादियों और तलाक के कारण पलक के बचपन को लेकर चिंतित थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 'पलक जब मुझे उस दौर में देखती थी तो मैं अक्सर सोचती थी कि उसका बचपन कैसा होगा। किसी तरह, उसने हर चीज को सकारात्मक रूप से लिया और खुद को अलग तरीके से ढाला।'

श्वेता तिवारी ने आगे कहा, 'मेरी परवरिश का काम और उसकी खुद की संवेदनशीलता ज्यादा है। वह खुद एक शक्तिशाली लड़की है, वह समझ गई है कि अगर आप खुद को हल्के में नहीं लेंगे तो कोई भी इसे हल्के में नहीं लेगा। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आपको उसे स्वयं ही सुलझाना होगा।' श्वेता ने बेटी पलक की तारीफ करते हुए कहा, 'इसलिए उसने मेरी यात्रा से भावनात्मक रूप से मजबूत बनना सीखा है। तो यही बात उसे मजबूत बनाती है, अब वह एक बहुत ही संवेदनशील बच्ची है।' श्वेता तिवारी मशहूर टेलीविजन अभिनेत्री हैं, जिन्हें मुख्य रूप से उनके लोकप्रिय टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। काम के मोर्चे पर, श्वेता तिवारी अगली बार रोहित शेट्टी, सुशांत प्रकाश और स्नेहा शेट्टी कोहली द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर सीरीज 'इंडिया एयर फोर्स' में दिखाई देंगी। इस सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और विवेक ओबेरॉय मुख्य भूमिका में हैं। यह रोहित शेट्टी पिक्चर्स और रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले निर्मित कॉप यूनिवर्स पर आधारित है। सात एपिसोड की सीरीज इसी साल अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी।

आखें नम... पदक न जीत पाने का गम

दिल्ली में विनेश फोगाट
का ग्रैंड वेलकम



विनेश फोगाट का नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, बजरंग-साक्षी से मिलकर हुई भावुक

नई दिल्ली, एर्जेसी। भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौट आई हैं। उनका नई दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। विनेश के स्वागत के लिए फैंस ढोल नगाड़ों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। वहीं, पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक भी एयरपोर्ट पर नजर आए। उनसे मिलते ही विनेश भावुक हो गईं और फूट फूट कर रोने लगीं। विनेश का गांव पहुंचने तक 20 जगहों पर स्वागत किया जाएगा। विनेश पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने से चूक गई थीं। महिलाओं की 50 किग्रा वर्ग के फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें बड़े

हुए वजन की वजह से डिसक्वालिफाई कर दिया गया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों ने एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विनेश को कंधे पर उठा लिया और कंधे पर उठाकर ही गाड़ी तक ले गए। इस दौरान भी विनेश का आंसू नहीं रुके। वह गाड़ी पर बजरंग और साक्षी के साथ खड़ी हुईं और रोती रहीं। विनेश ने कहा कि मैं पूरे देशवासियों को धन्यवाद कहती हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। वहीं, पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, 'विनेश ने देश के लिए जो किया है, वह बहुत कम लोग कर सकते हैं। उन्हें और अधिक सम्मान और सराहना मिलनी चाहिए। उन्होंने

पदक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।' वहीं, बजरंग पूनिया ने कहा— देशवासी उन्हें जबरदस्त प्यार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं देश ने उनका किस तरह स्वागत किया गया है। दरअसल, विनेश पेरिस में पदक से चूक गई थीं। उनका वजन फाइनल से पहले 100 ग्राम ज्यादा रहा था, जिसके बाद उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया था। फिर विनेश ने खेल पंचाट में भी संयुक्त रजत पदक देने की अपील की थी, लेकिन खेल पंचाट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया था। पदक न जीत पाने से दुखी विनेश ने कुश्ती से

संन्यास का एलान कर दिया था। यह उनका तीसरा ओलंपिक था। वहीं, साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने कहा, 'विनेश एक फाइटर थीं, हैं और रहेंगी। वह हमारे लिए एक चैंपियन हैं और हम एक चैंपियन की तरह उनका स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम उन्हें एक स्वर्ण पदक विजेता के रूप में मान रहे हैं। वह 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती थीं। उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा क्यों की, यह एक बड़ा सवाल है कि वह 50 किलोग्राम वर्ग में स्थानांतरित होने का क्या कारण था।

पीएम मोदी और भारतीय हाकी टीम



दिल्ली। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन मिलाजुला रहा। भारत ने इन खेलों में एक रजत और पांच कांस्य पदक समेत कुल छह पदक जीते। देश लोटने के बाद भारतीय एथलीट्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की। सभी एथलीट्स प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पीएम ने उन्हें संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम से भी बातचीत की और उनकी तारीफ की। साथ ही पीएम ने संन्यास ले चुके भारतीय गोलकीपर पीआर श्रीजेश से सवाल जवाब भी किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्हें सरपंच साहब नाम से भी बुलाया जाता है, उनकी जमकर तारीफ की। कमेंटेटर सुनील तनेजा ने हरमनप्रीत का सरपंच नाम काफी प्रसिद्ध कर दिया है। पीएम मोदी ने श्रीजेश से पूछा— आपने रिटायर होने का मन पहले ही बना लिया था या फिर बाद में? इस पर श्रीजेश कहते हैं— पिछले कुछ वर्षों से सोच रहा था। मेरे टीम वाले पूछ रहे थे कि बता दे भाई कब छोड़ेगा। 2002 में मैं पहली बार कैंप में गया और 2004 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जूनियर टीम के साथ, तब से मैं खेलता आ रहा हूँ और 20 साल से अपने देश के लिए खेल रहा हूँ तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म से संन्यास लेना है। ओलंपिक एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, जहां दुनियाभर के खेलों का मेला लगता है। मुझे इससे अच्छा मौका मिलता नहीं तो इसलिए ही निर्णय ले लिया। इसके बाद पीएम मोदी कहते हैं, 'ये टीम आपको मिस तो करेगी ही करेगी, लेकिन इस टीम ने आपकी विदाई शानदार की। ये पूरी टीम को बधाई है। सरपंच साहब ने अच्छा काम किया।' इसके बाद श्रीजेश कहते हैं— सच में, क्योंकि हम इसका

सपना ही देख सकते थे। हमलोग जब सेमीफाइनल हार गए थे तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये टीम जब पेरिस गई थी तो हमने उम्मीद ये की थी कि हम पेरिस में फाइनल खेलेंगे और ये टीम स्वर्ण पदक के लायक है। जब सेमीफाइनल हार गए थे, तो थोड़ा दर्द हुआ था सबको, लेकिन जब आखिरी मैच खेलने उतरे तो सभी ने कहा कि ये मैच श्रीजेश भाई के लिए जीतना है, तो मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात तो यही है कि 17 साल जो मेहनत मैंने भारत के लिए किया, इन साथियों ने मेरा साथ दिया और खासतौर पर ये मेरे लिए गर्व की बात है कि उस पोज़ियम पर अपनी टीम को खड़ा हुआ देख पाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम से पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की उम्मीद थी, स्वर्ण तो नहीं आया, लेकिन भारतीय टीम कांस्य पदक को बरकरार रखने में कामयाब रही है। भारत ने टोक्यो 2020 में 41 साल का पदक का सूखा समाप्त किया था और मनप्रीत सिंह की अगुआई में कांस्य पदक जीता था। अब तीन साल बाद भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता है। भारत ने कांस्य पदक के मुकाबले में स्पेन को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने 1980 में मॉस्को ओलंपिक के बाद से इन खेलों में अब तक स्वर्ण नहीं जीता है। ओलंपिक में जिस खेल में भारत को सबसे ज्यादा सफलता मिली है वो हॉकी ही है। भारत अब तक हॉकी में कुल 13 पदक जीत चुका है जिसमें आठ स्वर्ण, एक रजत और चार कांस्य पदक शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 52 साल बाद लगातार दो ओलंपिक में पदक जीते हैं। इससे पहले 1968 और 1972 में ऐसा हुआ था।



जर्सी की एक्सचेंज

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में जीते दो कांस्य पदक
मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर लिया बान्ज मेडल
मनु भाकर ने मोहम्मद कैफ के साथ जर्सी की एक्सचेंज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट का नई दिल्ली के ताज पैलेस में शानदार स्वागत हुआ। एक भव्य स्वागत समारोह पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जीतने वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किया गया, होस्ट किया। इस समारोह की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पेरिस ओलंपिक्स के डबल-मेडलिस्ट मनु भाकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के साथ जर्सी एक्सचेंज करती हुई नजर आ रही है। दरअसल, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिसमें पांच कांस्य पदक और एक सिल्वर मेडल शामिल रहा। मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलाया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर मिक्सड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ दूसरा कांस्य पदक अपने नाम किया। उनके अलावा स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता। भारतीय मैनस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा एकमात्र एथलीट रहे, जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद 15 अगस्त यानी आज इन एथलीट्स का दिल्ली के ताज पैलेस में भव्य स्वागत हुआ। जहां मनु भाकर और मोहम्मद कैफ एक दूसरे के साथ जर्सी एक्सचेंज करते हुए दिखे।

पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल 6 मेडल जीते जिसमें पांच कांस्य और एक सिल्वर मेडल शामिल रहा। मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक में पहला पदक दिलाया। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता और फिर मिक्सड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ दूसरा कांस्य पदक अपने नाम किया। उनके अलावा स्वप्निल कुसाले और अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता। भारतीय मैनस हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा एकमात्र एथलीट रहे, जिन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद 15 अगस्त यानी आज इन एथलीट्स का दिल्ली के ताज पैलेस में भव्य स्वागत हुआ।



दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक
बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन
ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा
हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर
गोरखपुर से मुद्रित एवं 665
बी गंगा टोला, निकट
जानकी बिल्डिंग मैटेरियल
बसरातपुर पश्चिमी, गोरखपुर
से प्रकाशित। पिन:- 273003

Tital code: UPHIN51019

बृजेन्द्र कुमार

मो. नं. 7307180148, 9170772370
Email- thenextpost01@gmail.com

नोट:- समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद
गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होंगे।